



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 12 नवम्बर, 2009/21 कार्तिक, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला— 2, 10 नवम्बर, 2009

संख्या: 1 (ए) 3-9/91-श्रम-I.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापन अधिनियम, 1969 (1970 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्ज रैडिसन जास होटल, शिमला को उक्त अधिनियम की धारा 29 (1) के प्रवर्तन से छूट प्रदान करती है और इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गज़ट) में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए महिला कर्मचारियों को निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करने के अध्यधीन रात की पारी में काम करना अनुज्ञात करती है :—

1. किसी भी महिला कर्मकार को स्थापन में मध्य रात्रि (12.00 से 6.00 प्रातः काल) के दौरान कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। उन्हें रात्रि में, अपराह्न 8.00 से मध्य रात्रि तक काम करना अनुज्ञात है;
2. किसी भी महिला कर्मचारी को अकेले रात्रि की पारी में काम पर नियोजित नहीं किया जाएगा;
3. स्थापन, रात्रि की पारी में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को उनके कार्य स्थान से उनके होस्टल/आवास और विपर्ययन, परिवहन प्रसुविधा उपलब्ध करवाएगा;
4. रात्रि में परिवहन के दौरान सशस्त्र सुरक्षा गार्ड सहित एक महिला अनुरक्षक यान में उपलब्ध करवायी जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाए कि महिला कर्मचारी को उस के घर द्वार से लिया जाए और उसके घर द्वार पर उतारा जाए;
5. भोजन का प्रबन्ध स्थापन द्वारा किया जाएगा ताकि महिला कर्मचारी रात्रि पारी के दौरान स्थापन के भीतर ही भोजन कर सकें; और
6. अनुरक्षक, चालक और सुरक्षा कर्मचारिवृन्द को नियोजित करने पूर्व उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन पुलिस के माध्यम से कर लिया जाएगा।

आदेश द्वारा,
हस्ता/—
सचिव।

Authoritative English text of this Department Notification No. 1 (A) 3- 9/ 91- Shram- I dated 10/11/2009 as required and clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla- 171002, 10th November, 2009

No. 1 (A) 3- 9/ 91- Shram- I.—In exercise of the powers conferred by the Section 27 of the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1969 (Act No.10 of 1970), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to exempt M/s Radisson Jass Hotel, Shimla from the operation of the Section 29 (1) of the said Act, and to permit women workers to work in the night shift for a period of one year from the date of publication of this Notification in the Official Gazette (e- gazette) subject to the fulfillment of following conditions:—

1. That no women worker shall be allowed to work in the establishment during the period from the Midnight (12:00 to 6:00 AM). They are allowed to work in the night from 8:00 PM to Midnight;
2. That no women worker shall be engaged alone to work in the Night Shift'
3. That the establishment shall provide transport facilities to the women workers working in the night shift from the work place to their hostel/ residence and vice- versa;

4. That during transportation in the night, a lady escort accompanied by the armed security guard shall be provided in the vehicle and it may be ensured that the lady employee is picked up and dropped at the doorstep;
5. That the arrangement for meals will be made by the establishment, so that the women workers can take their meals during the Night Shift inside the establishment it self; and
6. That the antecedents of the escort, driver and security staff shall be got verified through police before employing them.

By Order,
Sd/-
Secretary.

NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 8 th November, 2009

No. NES-F(10)5/2006.—In continuation of the Notification No. MPP-F(10)-15/2006 dated 16th September, 2009 issued by the Department of MPP and Power, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a Sub-Division level “Local Area Development Committee” (LADC) in respect of each Small Hydroelectric Projects upto 5MW being implemented in Public/Joint/private for the development of “Project Affected Areas” *i. e.* “ the areas/ villages surrounding falling in the catchment/watershed areas extending from the Reservoir to the Tail Race of the Project” as defined in the Hydro Power Policy of the Government of Himachal Pradesh.

2. The Sub Divisional Level Local Area Development Committee” (LADC), for each project shall be as under:—

1.	The Sub Divisional Officer (C), concerned Sub Division	Chairman
2.	Block Development Officer (Concerned) -do-	Member
3.	Tehsildar of the concerned area	-do-
4.	Representative of HEPs concerned Project	-do-
5.	Representative of HPSEB, concerned area	-do-
6.	Representative of Himurja, -do-	-do-
7.	Representative of PWD -do-	-do-
8.	Representative of IPH Deptt. -do-	-do-
9.	Representative of Forest Deptt. -do-	-do-
10.	Representative of Fisheries Deptt. -do-	-do-
11.	Pradhan(s) of affected Panchayat(s) -do-	-do-
12.	Superintendent (S. D. M. office)	Member Secretary

The Sub Divisional Officer may co-opt any other member or officer/official from the Deptt. of Education, Agriculture, Animal Husbandry, Social Justice & Welfare and Language Art and Culture or any other Department as per requirement of the project/area.

By Order,
Sd/-
Chief Secretary.

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 नवम्बर, 2009

संख्या : NES-F-(5) 5/2008.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मैसर्ज एन एस एल मसली पावर जैनरेशन प्रा. लि. (जो पहले न्यूजीविडु सीडस लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी), 905, नवम मंजिल, कंचन जंगा भवन, 18 बराखम्बा रोड, क्वाँट प्लेस, नई दिल्ली-110001 जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (ई) के अन्तर्गत एक निजी कम्पनी है के द्वारा अपने व्यय पर कम्पनी के प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल जिटाटा, मसली तथा खरोट, तहसील चिड़गांव, जिला शिमला हि0 प्र0 में मसली (5.00 मै.वा.) लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव: एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता एवं उप-मण्डलाधिकारी (ना.) रोहडू जिला शिमला हिमाचल प्रदेश को एतद्द्वारा भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का निर्देश दिया जाता है ।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता एवं उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) रोहडू जिला शिमला उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं ।

4. भूमि रूखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता एवं उप-मण्डलाधिकारी (ना.) रोहडू जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	रकवा (हैक्टेयर में)
शिमला	चिड़गांव	जिटाटा	793 / 1	00-00-16
			1092 / 1	00-03-98
			1082 / 1	00-01-82
			1082 / 3	00-00-63
			1084	00-01-84
			1085	00-02-70
			1086 / 1	00-00-50
			1088	00-03-70
			1089	00-03-24
			1090 / 1	00-02-48
			1091 / 1	00-00-28
			1120	00-02-64
			1119	00-05-56
			1133	00-02-98
			1147	00-02-96

			1134	00-01-90
			1117	00-01-53
			1116	00-01-36
			1115	00-01-93
शिमला	चिडगांव	मसली	287 / 2	00-00-54
			152 / 1	00-00-72
			153 / 1	00-01-05
			551	00-08-45
शिमला	चिडगांव	खरोट	732	00-01-40
			723 / 1	00-03-09
किता-25 कुल रकवा				00-57-44 हैक्टेयर

आदेश द्वारा,
हस्ता/-
मुख्य सचिव।

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 5 नवम्बर, 2009

संख्या : एल0एल0आर0-ई0 (9)-1/2007.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बददी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी0ई0ओ0) को, मोहाली से बददी को जोड़ने वाले एक्सप्रेस वे के सन्निर्माण के लिए पंजाब सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन तथा इससे सम्बन्धित अन्य सुसंगत दस्तावेजों को हस्ताक्षरित करने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत करती हैं।

आदेश द्वारा
हस्ता/-
विधि परामर्शी-एवं-सचिव।

Authoritative English Text of this Department Notification No. LLR-E (9)-1/2007 dated 5th November, 2009 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India.)

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 5th November, 2009

No. LLR-E(9)-1/2007.—In exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 299 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to authorise the Chief Executive Officer (C.E.O.) of Baddi- Barotiwal-Nalagarh Development Authority to sign and execute Memorandum of Understandings and its other relevant documents between the

Government of Punjab and Himachal Pradesh for the construction of Expressway along Mohali linking Baddi.

By Order,
Sd/-

L.R.-cum-Secretary.

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण मनीकरण

मनीकरण विशेष क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग के प्रकाशन वारे सूचना

एतद द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मनीकरण विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के क्षेत्र के लिए भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बन्धी मानचित्र को हिमाचल प्रदेश, नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का बारहवां अधिनियम) की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और जिसकी एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है :-

1. अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण -एवं- जिलाधीश, कुल्लू ।
2. सदस्य सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण -एवं- योजना अधिकारी, नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय, कुल्लू ।
3. प्रधान, ग्राम पंचायत, मनीकरण ।

यदि इस प्रकार किए गए भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग सम्बन्धी मानचित्र में कोई आपत्ति अथवा सुझाव हो तो लिखित रूप में अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मनीकरण एवं- जिलाधीश, कुल्लू, सदस्य सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मनीकरण -एवं- योजना अधिकारी, मण्डलीय नगर योजना कार्यालय, कुल्लू व प्रधान, ग्राम पंचायत, मनीकरण को हिमाचल प्रदेश राजपत्र में सूचना प्रकाशन की तारीख से तीन दिन की कालावधि के भीतर भेजे जाने चाहिए ।

भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बन्धी उक्त मानचित्र के सम्बन्ध में जो आपत्ति/सुझाव किसी भी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि से पूर्व प्राप्त हों अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मनीकरण द्वारा विचार किया जाएगा ।

स्थान : कुल्लू ।

26
अध्यक्ष,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मनीकरण
एवं जिलाधीश, कुल्लू ।

SPECIAL AREA DEVELOPMENT AUTHORITY MANIKARAN

NOTICE OF PUBLICATION OF EXISTING LANDUSE MAP FOR MANIKARAN SPECIAL AREA

Notice is hereby given that existing land use map of Manikaran Special Area has been prepared under Sub-Section (1) of Section-15 of the Himachal Pradesh , Town & Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) and copy thereof is available for inspection during the office hours in the following offices :-

1. Chairman, Special Area Development Authority,
Manikaran -cum-Deputy Commissioner, Kullu.
2. Member Secretary, SADA, Manikaran-cum-
Planning Officer, Divisional Town Planning
Office, Kullu (HP).
3. Pardhan, Gram Panchayat, Manikaran.

If there is any objection or suggestion with respect to the existing landuse map so prepared, it may be sent in writing to the Chairman, SADA, Manikaran- cum-Deputy Commissioner, Kullu, Member Secretary, SADA Manikaran -cum-Planning Officer, Divisional Town Planning Office, Kullu or Pardhan, Gram Panchayat, Manikaran, District Kullu (HP) within a period of 30 days from the date of publication of this notice in the Rajpatra of Himachal Pradesh.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said landuse map before the period specified above will be heard by the Chairman, Special Area Development Authority manikaran Special Authority.

Place : Kullu

Dated :


Chairman,
SADA, Manikaran-cum-
Deputy Commissioner, Kullu.

No: SADA (Manikaran)/09-53-88.....

Dated: 9.07.09

